से बढ़ोत्तरी कर रही है, उसके कारण, ये मिनी स्टील प्लांट्स कहाँ जाएं? जो हमारे स्टील मंत्री हैं, मैं माननीय इस्पात मंत्री जी से कहूंगा कि ये जो 185 स्टील प्लांट्स हैं, और इन 185 स्टील प्लांट्स में 50 हज़ार लोगों को रोज़गार देने की क्षमता है, उनका रोज़गार खत्म होता जा रहा है। उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है कि घरेलू लोगों के उपयोग की बिजली की दर तो बढ़ रही है, लेकिन साथ-साथ जहां उद्योगों में 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात है, वहां पर रोजगार देना तो दूर रहा, उन उद्योगों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय इस्पात मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नए राज्य के रूप में सृजन के बाद छत्तीसगढ़ सन् 2000 में अस्तित्व में आया था, उसको अब 16 साल हो गए। 16 साल के अंदर में वहां की जो सरकार रही हैं, उन सरकारों ने उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। मैं आपके माध्यम से माननीय इस्पात मंत्री जी का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम वहां जो उद्योग हैं, वे बंद नहीं होने पाएं। धन्यवाद।

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Motilal Voraji. Shri Ronald Sapa Tlau.

Condition of Highway roads in hilly States due to landslides

SHRI RONALD SAPA TLAU (Mizoram): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to raise a very important national issue.

While the 18,437 kms. highway in the ten hilly States of the country means a lifeline and survival to its people, it also ironically means a lot of death-traps and major mishaps that have happened since many years ago till very recently. Just recently, in Himachal Pradesh there was a complete blockade on two major National Highways. Then, just last week, on the Dimapur-Kohima-Maram highway, there was a blockade because of landslides again. The same thing happened in Uttarakhand; 29 people were killed and five were injured. At least, ten people died in massive landslides on the Arunachal highway.

Sir, all these horrifying landslides on our highways, besides bringing untold misery to the people, are also posing a threat to our security, compromising the security of the nation.

Sir, Government's post-landslide interventions many a time are too little and too late. The highway construction in the advanced countries include Breast Walls and Retaining Walls automatically in the construction package.

So, there are four measures that I would like the Government to take immediately to prevent further rampage. One, the Government norm for road construction today of

Rs. 5 crores per km. for 2-lane roads is too little. It is like a drop in a bucket. It is like prescribing one medicine to all patients. Secondly, the Government should request the State Governments of hilly States to immediately identify the landslide-prone areas, make realistic estimates and submit them to the Government so that necessary action can be immediately taken. Thirdly, the Mechanical Division of the CPWD should immediately deploy their machines. The fourth point is that the EPC, Engineering Procurement & Construction system, which is to be introduced shortly, need to take immediate measures to stop further devastation. And my last point is, unfortunately, the Rs. 55,000 crores budget for capital works for the year 2016-17, is too little, and we need a little more than that.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I too associate myself with what the hon. Member has mentioned.

SHRI P.L. PUNIA (Uttar Pradesh): Sir, I too associate myself with what the hon. Member has mentioned.

Prevalence of manual scavenging in the Country

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि देश में आज भी मैला ढोने वाले हैं, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। कल मैला ढोने वालों के पुनर्वास की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि राजधानी में मैला ढोने वालों का होना शर्मनाक है। ऐसी स्थिति यहां तलब है जबकि कानून में मैला ढोना प्रतिबंधित है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 233 मैला ढोने वाले हैं। दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में एक भी मैला ढोने वाले के न होने की बात कही है, जबकि आयोग उनके होने का दावा कर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. It is time for Question Hour now.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।